

तेज निर्णय की बानगी तबादले

डॉ. राजेश राजौरा का मंत्रालय से बाहर जाना तय था

अभी और देखने मिलेंगे बड़े निर्णय

कन्हैया लोधी

भोपाल, 25 जुलाई. मप्र कौंडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनुराग जैन को नीति आयोग का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाए जाने के बाद राज्य सरकार ने बिना देर किए अशोक बर्णवाल को नया मुख्य सचिव बनाने के आदेश जारी कर दिए. इस निर्णय में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ ही अनुराग जैन की भी बड़ी भूमिका बताई जाती है.

अशोक बर्णवाल का शैली साइलेंट वर्कर की है, वे बिना किसी शोर-शराबे के तेज निर्णय लेने वाले अफसरों में उनकी गिनती है. अब प्रदेश का प्रशासनिक मुखिया बनने के बाद उन्होंने अपनी वर्किंग स्टाइल की बानगी दिखाना शुरू कर दिया है. शुक्रवार देर रात किए गए आईएएस के तबादले इसकी एक बानगी है कि तेज निर्णय कैसे होते हैं. अब आने वाले दिनों में प्रशासनिक निर्णय तेजी से लिए जाएंगे. यह भी साफ संदेश दिया गया है.

भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 1991 बैच के अधिकारी अशोक बर्णवाल को 22 जुलाई को मप्र का मुख्य सचिव बनाया गया, 23 जुलाई को उन्होंने नया दायित्व संभाल लिया. ठीक अगले दिन ही उन्होंने बड़े स्तर पर प्रशासनिक तबादले किए. सबसे पहला आर्डर दिन में लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव सुखबीर सिंह का रहा. बर्णवाल मुख्य सचिव बनने से पहले जिन विभागों की जिम्मेदारी



संभाल रहे थे, उस जिम्मेदारी को देने के लिए उन्होंने सुखबीर सिंह का चयन किया. सुखबीर सिंह अब लोक निर्माण विभाग के साथ ही लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग जैसे बड़े विभाग की जिम्मेदारी भी संभालेंगे. सुखबीर सिंह को भी साइलेंट वर्कर के रूप में भी शुमार किया जाता है. वे भी बिना-किसी शोर-शराबे के परिणाम देने में लगे रहते हैं.

इधर अशोक बर्णवाल के मुख्य सचिव बनने के बाद 1990 बैच के डॉ. राजेश राजौरा का मंत्रालय से बाहर जाना तय हो गया था, उन्हें नरेशा प्रशासन अकादमी में डीजी बना दिया गया है. वे बर्णवाल से एक बैच सीनियर हैं. मंत्रालय में मुख्य सचिव से सीनियर अफसरों को पदस्थ नहीं किया जाता, लिहाजा डॉ. राजौरा को मंत्रालय से बाहर कर दिया गया. इसका सबसे बड़ा फायदा 1995 बैच के सचिन सिन्हा को मिला, उनकी एक बार फिर मुख्य धारा में वापसी हो गई है.

अभी और होंगे तबादले

बताया जा रहा है कि नए मुख्य सचिव अब मंत्रालय से लेकर मैदान तक नई जमावट करेंगे, हालांकि मैदान में ज्यादातर नई जमावट बन चुकी है. फिर भी कुछ अफसरों को मैदान से हटाकर दूसरी जगह पोस्टिंग की जाएगी. इसमें परफॉर्मंस सबसे अहम होगा. परफॉर्मंस की कसौटी पर खरे नहीं उतरने वाले अफसरों को मैदानी पोस्टिंग से हटाया जाएगा. वहीं मंत्रालय में भी अफसरों की जिम्मेदारी में फेरबदल हो सकता है. इनमें प्रमुख सचिव, सचिव, अपर सचिव के साथ ही विभागाध्यक्ष स्तर के अधिकारी भी शामिल होंगे.

बर्णवाल को मिल सकता है एक्सटेंशन

नए मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल का रिटायरमेंट जनवरी 2027 में है. यानी वे अगले 6 माह तक मप्र के मुख्य सचिव बने रहेंगे. किसी अधिकारी को बतौर मुख्य सचिव परफॉर्मंस दिखाने के लिए 6 माह का समय कम माना जाता है. ऐसे में उन्हें एक्सटेंशन मिलना तय माना जा रहा है. अब ये एक्सटेंशन 6 माह का होगा या फिर सीधे एक वर्ष के लिए मिलेगा, इसे लेकर अभी संशय है. बर्णवाल को एक्सटेंशन मिलता है तो फिर डॉ. राजौरा के मुख्य सचिव बनने की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी. ये इसलिए कि डॉ. राजौरा मई 2027 में रिटायर हो जाएंगे. डॉ. राजौरा पहले अनुराग जैन को मुख्य सचिव बनाए जाने के दौरान भी सीएस पद के तगड़े दावेदार थे.

वे अब तक महानिदेशक प्रशासन अकादमी की कमान संभाल रहे थे, लेकिन अब एसीएस पीएचई के रूप में मंत्रालय में उनकी वापसी हो गई है. पीएचई में जल जीवन मिशन का बड़ा काम चल रहा है, जिसे वर्ष 2028 तक पूरा करना है, ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाला मिशन है.

प्रधान का इस्तीफा छात्र हितों की जीत

भिण्ड. नीट पेपर लोक मामले को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में चल रहे आंदोलन के समर्थन में मध्यप्रदेश के भिण्ड में भी पिछले चार दिनों से लगातार प्रदर्शन के दौरान शनिवार को शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की खबर मिलते ही आंदोलनकारियों ने इसे छात्र हित की लड़ाई की जीत बताया. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि युवाओं को एकजुट आवाज और देशभर में हुए आंदोलनों का असर देखने को मिला है. उनका कहना था कि अब छात्रों को न्याय दिलाने और परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने चाहिए. छात्र संगठनों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया.

सैट्टिक टैंक में गिरने से 3 साल के मासूम की मौत

खंडवा, 25 जुलाई. तीर्थनगरी ऑंकारेश्वर में व्यवस्थाओं और विकास के नाम पर 'सिस्टम' कितना खोखला और जानलेवा हो चुका है, इसका उदाहरण खंडवा जिले में देखने मिला. महाराष्ट्र के नागपुर से भगवान के दर्शन की आस लेकर आए एक परिवार को नगर परिषद के भ्रष्ट और लापरवाह सिस्टम ने ज़िंदगी भर का जख्म दे दिया.

ब्रह्मपुरी पार्किंग में नगर परिषद की घोर लापरवाही के कारण एक 3 साल का मासूम तनुपु खुले सैट्टिक टैंक में गिर गया और तड़प-तड़प कर उसकी मौत हो गई.

कैसे हुआ हादसा? :

नागपुर निवासी कैलाश उसराटे अपने परिवार के साथ बस से ऑंकारेश्वर पहुंचे थे. बस ब्रह्मपुरी पार्किंग में रुकी. अंधेरा था और 3 साल का तनुपु बस से उतरते ही थोड़ा आगे दौड़ा. उसे क्या पता था कि जिस भरती पर वह दर्शन करने आया है, वहां प्रशासन ने मौत का जाल बिछा रखा है. अंधेरे में मासूम सीधे उस खुले सैट्टिक टैंक में जा गिरा जिसे नगर परिषद ने अपनी तथाकथित 'कार्रवाई' के बाद खुला छोड़ दिया था. पिता ने जान की परवाह किए बिना छलांग लगाई, लेकिन मासूम को बचाया न जा सका.

इटारसी में प्रगति समीक्षा बैठक आयोजित

भोपाल,25 जुलाई. विद्युत लोको शेड, इटारसी में अप्रैल से जून तिमाही की राजभाषा प्रगति समीक्षा बैठक आयोजित की गई.

बैठक में राजभाषा संपर्क अधिकारी एवं सहायक मंडल सामग्री प्रबंधक सत्येन्द्र चौधरी, मंडल राजभाषा अधिकारी बृजेंद्र कुमार, सहायक मंडल विद्युत इंजीनियर हरिनारायण सिंह यादव, वरिष्ठ अनुवादक सुधीर कुमार एवं राजेश कुमार, तथा राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सचिव सचिन सिंह तोमर सहित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे. बैठक में सत्येन्द्र चौधरी ने राजभाषा संबंधी आंकड़ों के सही संधारण पर जोर देते हुए कहा कि हिंदी के प्रयोग में अपेक्षित प्रगति नहीं दिख रही है. उन्होंने



मंडल राजभाषा अधिकारी बृजेंद्र कुमार ने विद्युत लोको शेड, इटारसी के राजभाषा कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि इसकी प्रशंसा मंडल स्तर पर भी होती है. उन्होंने पीसीडीओ/एमसीडीओ जैसे अंग्रेजी प्रारूपों को हिंदी में उपलब्ध कराने के लिए उच्च स्तर पर पहल का आश्वासन दिया. सहायक मंडल विद्युत इंजीनियर हरिनारायण सिंह यादव ने कहा कि अन्य शेडों की तुलना में इटारसी का प्रदर्शन बेहतर है और हिंदी के प्रयोग को और व्यापक बनाने की आवश्यकता है. बैठक के अंत में सचिव सचिन सिंह तोमर ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए राजभाषा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निरंतर सहयोग की अपेक्षा जताई.

अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अधिक समर्पण के साथ राजभाषा

कार्यों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया.

मध्यप्रदेश में भारी बारिश की संभावना



35 जिलों में बारिश का अलर्ट

भोपाल, 25 जुलाई . मध्यप्रदेश में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है. मौसम विभाग ने प्रदेश के 35 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है.

अगले चार दिनों तक कई हिस्सों में तेज से भारी बारिश होने

की संभावना है. अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मिलने तथा प्रदेश से मानसून ट्रफ गुजरने के कारण वातावरण में 80 से 95 प्रतिशत तक आर्द्रता बनी हुई है, जिससे पूर्वी, मध्य और दक्षिणी जिलों में भारी बारिश हो सकती है. निचले इलाकों में जलभराव और स्थानीय बाढ़ जैसी स्थिति बनने की आशंका, लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

मध्यप्रदेश में 200 नए सांदीपनि विद्यालय और बनेंगे : नागर सिंह

आगर मालवा, 25 जुलाई. मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री एवं आगर मालवा जिले के प्रभारी नागर सिंह चौहान ने शनिवार को आगर मालवा, सुसुरे एवं नलखेड़ा में 111.40 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित सर्वसुविधायुक्त तीन सांदीपनि विद्यालय भवनों का रिमोट का बटन दबाकर लोकार्पण किया और कहा कि प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है.

चौहान ने कहा कि राज्य में आज 14 हजार करोड़ रुपये की लागत से 370 सांदीपनि विद्यालय भवनों का लोकार्पण किया जा रहा

है तथा राज्य में 200 नए सांदीपनि विद्यालय भी बनाए जाएंगे. उन्होंने विद्यालयों का निरीक्षण कर उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया और इन्हें भावी पीढ़ी के उज्ज्वल भविष्य का मजबूत आधार स्तंभ बताया. इस अवसर पर गत बोर्ड परीक्षाओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं रचना, खुशी, संजना, रानी तथा शव-प्रतिशत परीक्षा परिणाम देने वाले विद्यालयों के प्राचार्यों, संस्था प्रमुखों और शिक्षकों को शॉल, शीफल एवं प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया गया. इससे पूर्व प्रभारी मंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया. कलेक्टर प्रीति यादव ने उनका स्वागत किया.

धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा छात्रों की जीत

विशेष संवाददाता

भोपाल, 25 जुलाई. मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे को देश के करोड़ों छात्रों, अभिभावकों और युवाओं की ऐतिहासिक जीत बताया है. उन्होंने आरोप लगाया कि जनता के लगातार बढ़ते दबाव के कारण केंद्र सरकार को यह फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ा.

जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार के अहंकार और तानाशाहीपूर्ण रवैये के कारण शिक्षा व्यवस्था गंभीर संकट में पहुंच गई. उनका आरोप है कि बार-बार प्रश्नपत्र लीक होने और 50 से अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं के निरस्त होने से लाखों

यह इस्तीफा केवल शुरुआत है और कांग्रेस तब तक अपना संघर्ष जारी रखेगी, जब तक दोषियों की जवाबदेही तय नहीं हो जाती तथा ऐसी व्यवस्था स्थापित नहीं होती, जिसमें छात्रों का भविष्य भ्रष्टाचार नहीं बल्कि उनकी प्रतिभा और मेहनत के आधार पर तय हो. उन्होंने दावा किया कि देश का युवा अब जाग चुका है और शिक्षा की शुधिता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं करेगा.



विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है. विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं से करोड़ों अभ्यर्थियों और उनके परिवारों को मानसिक एवं आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा. केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लोकतांत्रिक जनदबाव की ताकत का प्रमाण है. इसे किसान आंदोलन के बाद केंद्र

सरकार द्वारा कृषि कानून वापस लेने की घटना से जोड़ते हुए पटवारी ने कहा कि जनता की एकजुट आवाज अंततः सरकार को झुकने पर मजबूर करती है. उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी का भी उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने संसद और संसद के बाहर लगातार छात्रों के मुद्दों को उठाया.

सावित्री, विजयवर्गीय ने टांडा रोड रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण

धार 25 जुलाई. केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री तथा धार-महू लोकसभा क्षेत्र की सांसद सावित्री ठाकुर ने शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र के गंधवानी विधानसभा अंतर्गत निर्माणधीन इंदौर-छोटा उदयपुर रेल परियोजना के तहत विकसित किए जा रहे टांडा रोड रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया.

इस दौरान उनके साथ मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री एवं धार जिले के प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे.

सावित्री ठाकुर और विजयवर्गीय ने निरीक्षण के दौरान रेलवे विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्टेशन निर्माण और

परियोजना की प्रगति से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की. ठाकुर ने चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का सूक्ष्मता से अवलोकन किया और रेलवे अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर रह हाल में पूरे किए जाएं. उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए, ताकि क्षेत्रवासियों को शोषण ही आधुनिक, सुगम और सुरक्षित रेल सुविधाओं का लाभ मिल सके. प्रभारी मंत्री विजयवर्गीय ने परियोजना की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए रेलवे विभाग को समयबद्ध कार्य सुनिश्चित करने को कहा.

जेएनपीए : 43 आबकारी अधिकारी पासआउट

विशेष संवाददाता

भोपाल/सागर, 25 जुलाई. जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी (जेएनपीए), सागर में आयोजित दो माह के आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल समापन पर जिला आबकारी अधिकारी एवं आबकारी उप निरीक्षक के द्वितीय बैच के 43 प्रशिक्षु अधिकारियों का शनिवार को पासआउट समारोह आयोजित किया गया.

इस अवसर पर सभी अधिकारियों ने राष्ट्र की सेवा, कानून के निष्पक्ष पालन तथा जनहित में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करने की शपथ ली. 18 मई से 23 जुलाई 2026 तक चले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षुओं को आबकारी

मंत्रालय के गलियारे से यूसीसी पर चर्चा और अधिकारी दीर्घा में सूनापन



कन्हैया लोधी

मप्र सरकार ने सदन में यूसीसी बिल पारित करा लिया. इस विधेयक पर सदन में सार्थक बहुसं की जरूरत थी, लेकिन हंगामे के कारण वह हो नहीं सकी. सदन में बिल पर चर्चा के दिन सदस्यों की भरपूर उपस्थिति बनी रही. भाजपा के सचेतक सतर्क थे और विधायकों को सदन में बने रहने के निर्देश थे, वहीं दूसरी तरफ सदन में अधिकारी दीर्घा में इस दौरान सूनापन साफ नजर आया. इस पर जब पक्ष-विपक्ष में जमकर बहस हो रही थी और हंगामे की स्थिति बन रही थी,

ये बाज नहीं आएंगे

कांग्रेस कोई कार्यक्रम करे और वहां हंगामा नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता. पिछले दिनों भी राजधानी में एक प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ऐसा बर्ताव किया कि कई सीनियर नेताओं के पास बगले झांके के अलावा कोई विकल्प नहीं था. एक कार्यकर्ताओं के समूह ने दूसरे पर जमकर हाथ साफ किए. हाथ साफ करने में कोई कंजूसी नहीं की, पूरी दरियादिली दिखाई. ऐसे में दूसरे के पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह गया था. बहरहाल इस घटना ने जमकर सुर्खियां बटोरी. कहते हैं ना कि बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा. बहरहाल ये कार्यकर्ता अपने पुराने रवैये से बाज नहीं आ रहे हैं .

तब दीर्घा में कोई बड़े सीनियर अफसर नहीं थे. केवल मातहत अफसरों ने मोर्चा संभाल रखा था, जबकि सरकार ने पहले ही अफसरों को उपस्थिति के लिए ताकौद कर रखा था.

आदेश से पहले ही सामान समेटने लगे साहब

पिछले दिनों मंत्रालय में प्रशासनिक स्तर पर जो बड़े घटनाक्रम हुए, उसकी भनक एक ताकतवर अफसर को पहले ही लग गई थी. उन्हें अंदेशा हो गया था कि जल्द ही उन्हें यहां से रवानगी देना पड़ेगा. लिहाजा साहब ने पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी. साहब आर्डर से पहले ही जरूरी कागज और सामान समेटने लगे थे, वहीं गैरजरूरी के डिस्पोजल में लगे थे. वे अब कुछ हद तक दार्शनिक भी दिखने लगे हैं. भाग्य और विधाता के लेख को वे भी बड़े शिद्दत से मानने लगे हैं .

ज्यादा कॉकरोच पैदा न हों, सतर्क रहा प्रशासन

दिल्ली के जंतर-मंतर में तो देशभर के कॉकरोच इकट्ठे होते लगे थे, इतना बड़ा देश तो फिर भला कॉकरोचों की संख्या कम कैसे हो सकती है ? बहरहाल मप्र में भी कहीं-कहीं कॉकरोच दिखने लगे थे. ये कॉकरोच कुछ ज्यादा ही पैदा न हो, इसलिए सरकार का पुलिस और प्रशासनिक तंत्र चौकता बना हुआ था. ये इसलिए कि सरकार इस मामले में उपद्रव बढाश्त करने के मूड में नहीं थी. वह तो शुक्र है कि कॉकरोचों का संख्या बढने से पहले ही समस्या का समाधान खोज लिया गया. इससे सरकार के साथ पुलिस और प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है .

पांच युवकों की मौत दुर्घटना से नहीं जानबूझ कर डम्पर से कुचल कर की हत्या : एसपी

नरसिंहपुर. जिले के सुआतला पुलिस थाना के हाथीनाला वाटरफॉल में पिकनिक मना कर वापस आते समय 19 जुलाई को पांच युवकों की मौत डम्पर के टकराने पर हो गई थी और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था. इस मामले में पुलिस अधीक्षक (एसपी) ऋषिधर मीना ने शनिवार को पत्रकार वार्ता में खुलासा किया कि इन युवकों की दुर्घटना से मौत नहीं हुई थी बल्कि सुनियोजित तरीके से जानबूझ कर डम्पर से कुचल कर मारा गया है. इस मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है वहीं चार वाहन जब्त किये गये हैं. गौरतलब हो कि जबलपुर जिले के निवासी राजेश पटेल (23), वीरेंद्र लोधी (20), राजपाल लोधी (21), जयपाल लोधी (30), और नीरज लोधी (25) की मौत डम्पर से कुचल कर हुई थी.



अभिनियम, विधिक प्रक्रियाओं, अपराध विवेचना, नेतृत्व क्षमता, अनुशासन, शारीरिक दक्षता, फौलड क्राउड, व्यावहारिक पुलिसिंग तथा पेशेवर कौशल का व्यापक प्रशिक्षण दिया गया, ताकि वे अपने दायित्वों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकें.

समारोह की अध्यक्षता जेएनपीए की पुलिस अधीक्षक प्रतिमा पटेल ने की. कार्यक्रम को शुरुआत आकर्षक पॉसिंग आउट

परेड से हुई, जिसमें प्रशिक्षुओं ने अनुशासन, आत्मविश्वास और उत्कृष्ट समन्वय का प्रदर्शन किया. पुलिस अधीक्षक ने परेड की सलामी ली तथा सभी प्रशिक्षुओं को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. प्रशिक्षण के दौरान शैक्षणिक प्रदर्शन, शारीरिक प्रशिक्षण, फायरिंग, परेड तथा विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को प्रमाण-पत्र और पुरस्कार प्रदान

पेज एक का शेष

पहली बार राजनीतिक दबाव में सरकार

का काम विपक्ष, विशेषकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आक्रामक तेवरों ने किया. राहुल गांधी ने जिस तरह सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को कटघरे में खड़ा किया, लाठीचार्ज और पैलेट गन से घायल छात्रों के साथ मीडिया से रूबरू होकर सीधे सरकार की साख पर प्रहार किया, उसने विपक्ष की नई और मजबूत स्थिति को रेखांकित किया. संसद में चर्चा को रोकने की चेतावनी और धर्मेन्द्र प्रधान की बख्शीस्वगी से कम कुछ भी मंज़ूर नहीं का उनका अडिगल और स्पष्ट रुख रंग लाया. विपक्ष ने इस मुद्दे को सीधे मोदी के गिरते विश्वास और सरकार की गिरती साख के नैरेटिव से जोड़ दिया, जिससे सरकार के लिए इस संकट को टालना असंभव हो गया. वरिष्ठ भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी का यह बयान कि देर आए, दुरुस्त आए इस बात की तस्दीक करता है कि सरकार के भीतर भी इस अख्यवस्था को लेकर गहरी बेचैनी थी. इतना ही नहीं इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत और सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी इसका विकेंद्रीकरण था. जब तक यह आंदोलन दिल्ली तक सीमित था, तब तक सरकार के 'चुनिंदा तत्वों का विरोध' कहकर टालती रही. लेकिन इंटेलिजेंस और सरकार की आंतरिक रिपोर्टों ने इस इस्तीफे को अपरिहार्य बना दिया. अदरूनी रिपोर्टों में स्पष्ट चेतावनी दी गई थी कि यदि देश के छोटे शहरों में फैला यह छात्र आंदोलन और लंबा खिंचा, तो यह 1973 के गुजरात के मोरबी छात्र आंदोलन या 1974 के जेपी आंदोलन जैसा रूप ले सकता है, जिसने तत्कालीन सरकारों को उखाड़ फेंका था .

छात्रों के आगे झुकी सरकार, धर्मेन्द्र का इस्तीफा

को बहाइयां दी. केद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जेपी नट्टा और सीजेपी प्रवक्ता सीरम दास, आशुतोष रांका ने संयुक्त प्रेस कॉन्फेंस की. सीजेपी ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया है . सीजेपी ने कहा पिछले कुछ दिनों में सरकार से 3 बार बातचीत हुई, हमारी तीनों मांगें मान ली गई हैं. वहीं, सीजेपी ने प्रदर्शनकारियों से घर वापस लौट जाने का आग्रह किया. सीजेपी ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर जारी धरना तुरंत प्रभाव से खत्म कर दिया. सीजेपी ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण तरीके से अपने घर लौटने का आग्रह किया .